(घ) और (ङ) निजी क्षेत्र में परियोजना का क्रियान्वयन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और मै॰ नय प्रकाश इंडस्ट्रीज लि॰ के बीच एक समझौता ज्ञापन निष्पन्न किया गया है। प्रवर्तकों ने सूचित किया है कि स्थल पर कार्य 1.1.98 से आरंभ करने तथा 31.12.2002 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

विन्ध्याचल विद्युत परियोजना की पुनर्वास योजना

3600. **श्री जगन्नाथ सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की विन्ध्याचल विद्युत परियोजना में व्यापक पुनर्वास कार्य योजना को कार्यान्वित करने एवं विस्थापितों को राहत दिलाने संबंधी समस्या के बारे में एक स्थानीय गैर-सरकारी संगठन ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ऊर्जा मंत्रालय तथा विश्व बैंक को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे; और

(ख) यदि हां, इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) मध्य प्रदेश के सीधी जिले के विंध्याचल क्षेत्र के कई गैर-सरकारी संगठन सक्रिय हैं जहां राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने एक सुपर ताप विद्युत केंद्र यथा विंध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना स्थापित की है। समय-समय पर गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों में उठाए गए मुद्दों पर परियोजना प्राधिकारियों द्वारा गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ तथा जब भी आवश्यकता होती है, भू-विस्थापितों, एनजीओ, राज्य सरकार तथा एनटीपीसी के प्रतिनिधियों की ग्राम विकास सलाहकार समिति की बैठकों में विचार-विमर्श किया जाता है। परियोजना प्राधिकारी भी जब कभी संभव होता है, अपेक्षित कार्रवाई करते हैं।

परियोजना के चरण-I के लिए कुल 2330 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) को मुआवजा प्राप्त हुआ है। भू-विस्थापितों के लिए आरंभ किए गए विभिन्न पुनर्वास संबंधी उपायों में विंध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना में नियमित रोजगार, संविदात्मक ऐजेंसियों के जरिये रोजगार, छोटी-मोटी संविदाएं, वेंडरों के लाइसेंस प्रदान करना, विभिन्न व्यवसायों जैसे बढ़ईगिरि, टंकन, वेल्डिंग, सिलाई, कालीन-बुनाई इत्यादि में प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। परियोजना के चरण-2 के लिए कुल 824 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों ने मुआवजा प्राप्त किया है। इनमें से 226 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों ने क्षेत्र को छोड़ दिया है जब कि शेष 598 परियोजना प्रभावित व्यक्ति एनटीपीसी द्वारा क्रियान्वित की जा रही पुनर्वास कार्य योजना में शामिल हैं।

Power connections to Tribal Households

3601. SHRI AHMED PATEL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have issued any guidelines to the states for providing power connections to tribal households on priority;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether power connections were provided to tribal households on priority in Gujarat during the last three years;

(d) if so, the details thereof, yearwise; and

(e) by when Government propose to provide power connections to all the tribal households in Gujarat?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) and (b) Providing power connections to tribal households is regulated by the priority laid down by the various State Governments. However, to improve the quality of life. Government of India through Rural Electrification Corporation provides grants to the States for release of single-point light connections to the households of rural poor below the poverty line, including those belonging to Tribals and other weaker sections of the society. Presently the amount of grant is Rs. 1000/- per connecton with meter and Rs. 800/- per connection without installation of meter.

(c) As informed by Gujarat Electricity Board, there is no provision for giving priority to release household connections to tribals in case of a general demand. However, the State Government is

operating the Kutir Jyoti scheme for giving household connections to the tribal families, limited to tribal pockets only. These connections are being given to tribal households whose yearly income is less than Rs. 11.000/- and the house is situated within 30 meters radius from the nearby LT distribution network. The connections are being given alongwith the internal wiring for one point.

(d) The year-wise details for the last three years for Kutir Jyoti Programme in Gujarat is as under:

Year	Nos.
1994-95	10.000
1995-96	10.000
1996-97	10.000

(e) According to Gujarat Electricity Board, release of power connections to all the tribal households in Gujarat is being planned by them according to the availability of funds.

Acquisition of Land by NTPC in Orissa

3602. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the total land accuired by the National Thermal Power Corporation (NTPC) for its projects in Orissa;

(b) the year of the acquisition and the number of people affected thereby; and

(c) the details regarding compensasion paid to the displaced people?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) and (b) National Thermal Power Coporation (NTPC) had acquried about 3685 acres of land for their Talcher Super Thermal Power Project in Orissa. The land acquisition was effected during the period July, 1988 to August, 1996. The number of substantially affected families by the land acquisition is 1632.

(c) The total compensation deposited by NTPC with Government of Orissa from March, 1987 to May, 1996 was Rs. 8,73,32,185/- inclusive of 20% establishment charges.

Restructuring of Central Electricity Authority

3603. SHRI AMAR SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have decided to restructure the Central Electricity Authority which has become redundant in the present context;

(b) if so, the details thereof; and

(c) by when it is proposed to be restructured and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) to (c) The Government of India in the Ministry of Power had appointed Administrative Staff College of India, Hyderabad to conduct a study on restructuring the Regulatory System of Power Sector in India. The final Report of the study submitted by the ASCI is under consideration of the Government.

पावरग्रिड कारपोरेशन द्वारा बाण्ड जारी किए जाना

3604. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवेः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में विशेषकर त्रिपुरा में विद्युत परियोजनाएं लगाने हेतु घरेलू बाजार से धनराशि जुटा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा पावर ग्रिड कारपोरेशन को बाण्ड जारी कर बाजार से धनराशि जुटाने हेतु प्राधिकृत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो पावरग्रिड कारपोरेशन द्वारा घरेलू बाजार से धनराशि जुटाने हेतु अब तक कितनी धनराशि के बाण्ड जारी किए गए हैं; और

(घ) इन संसाधनों का उपयोग कर त्रिपुरा में आरंभ की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम त्रिपुरा समेत देश में